

गंगा एक्सप्रेसवे से सालाना होगी 30 हजार करोड़ की बचत

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ: मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाले 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में माल ढुलाई का समय काफी कम होने की उम्मीद है। सरकार और उद्योग जगत के अनुमानों के अनुसार इससे हर वर्ष 25 से 30 हजार करोड़ रुपये तक की लाजिस्टिक्स की बचत हो सकती है। इसके साथ ही एक दर्जन से अधिक जिलों में औद्योगिक और वेयरहाउसिंग गतिविधियों को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

छह लेन वाला यह एक्सप्रेसवे 12 जिलों से होकर गुजरता है और पश्चिमी तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच एक बड़े लाजिस्टिक्स व औद्योगिक कारिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। औद्योगिक आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में हर वर्ष करीब 245 से 260

पूरी खबर पढ़ने
के लिए स्कैन करें
क्यूआर



मिलियन टन आंतरिक माल ढुलाई होती है, जिसमें खाद्यान्न, निर्माण सामग्री और खुदरा सामान प्रमुख हैं। वहीं राज्य से बाहर भेजे जाने वाले माल की मात्रा 135 से 150 मिलियन टन के बीच आंकी गई है।

औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी' ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे राज्य की अर्थव्यवस्था में नया अध्याय साबित होगा। इससे औद्योगिक विकास, लाजिस्टिक्स, कृषि, पर्यटन और रोजगार सृजन की गति बढ़ेगी। उन्होंने कहा, 'यह सिर्फ सड़क परियोजना नहीं बल्कि एकीकृत मैनुफैक्चरिंग और लाजिस्टिक्स कारिडोर है। इसके उपयोग से माल परिवहन

तेज गति से होगा और ट्रांसपोर्ट व लाजिस्टिक्स लागत कम होगी जिससे हर साल 25 से 30 हजार करोड़ रुपये की बचत संभव है।'

मंत्री के अनुसार, एक्सप्रेसवे कारिडोर के किनारे अब तक 46,660 करोड़ रुपये के 987 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। इसके तहत 6,507 एकड़ में 12 औद्योगिक नोड विकसित किए जा रहे हैं। मैनुफैक्चरिंग, टेक्स्टाइल, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा, इलेक्ट्रानिक्स, वेयरहाउसिंग और ई-कामर्स जैसे क्षेत्रों को इससे विशेष लाभ मिलने की संभावना है। ब्लू डार्ट के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी दीपांजन बनर्जी ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे लाजिस्टिक्स संचालन की तस्वीर बदल देगा। अब तक एनसीआर से पूर्वी उप्र को जोड़ने वाला कोई निर्बाध कारिडोर नहीं था।